RAJYA SABHA

Friday, 13th February 1959

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

RESOLUTION *RE* APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO CONSIDER AND MAKE RECOMMENDATIONS AS TO THE TRADES AND INDUSTRIES WHICH SHOULD BE NATIONALISED.

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : आदरणीय सभापति जी, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं जो इस प्रकार है :—

"इस सभा की यह सम्मति है कि देश की वर्तमान स्थिति का ध्यान रखते हुए किन किन उद्योगों तथा व्यापारों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये इस पर विचार करने तथा सिफारिशें करने के लिये सरकार को संसद् सदस्यों तथा इस विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये ।"

मैंने जो यह प्रस्ताव पेश किया है वह केवल इस कारण पेश किया है कि सरकार की नीति इस विषय में स्पष्टतया निर्धारित हो जाये ताकि जो जनता के दिल में बाज बाज वक्त कुछ शंकायें और कुशंकायें पैदा होती हैं उन के पैदा होने का मौका न मिले । राष्ट्रीयकरण से मेरा मतलब यह है कि हम को यह देखना है कि ऐसे उद्योग धंधे जो राष्ट्रीय कैरेक्टर के हैं उन को हम किस प्रकार सरकार द्वारा संचालित कर सकते हैं ? दूसरे माने में हम यह कह सकते है कि ऐसी undertakings which are public owned and are national in character. राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य केवल यह रहता है कि उस में जनता की भलाई निहित रहती है । प्राइवेट इंटरप्राइज जो रहते हैं उन में जहां निजी लाभ की और ज्यादा ध्यान दिया जाता है वहां ऐसे सरकारी संचालित कार्यों में विशेषत: जनता की भलाई का ध्यान रहता है । इसी दृष्टि से मैंने इस प्रस्ताव को रखा है ।

जब हम सरकार द्वारा ऐसे राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यही होता है कि ऐसे धंधे जो भी हों वे पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किये जायें । पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई चीज कंट्रोल की जाती है तो उस के भी कई प्रकार रहते हैं । एक प्रकार तोऐ सा रहता है कि जिस में मिनिस्टर बतौर एजेंट पार्लियामेंट के काम करता है । एक ऐसा रहता है कि जो डाइरेक्ट पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता है या जो पार्लियामेंट के द्वारा कमेटी बनाई जाती है उस के द्वारा वह कंट्रोल किया जाता है । जो मिनिस्टर द्वारा कंट्रोल किये जाते हैं उन में भी आम तौर पर दो भेद रहते है, एक तो वह है जिस के द्वारा सिविल सर्विस का पूरा कंट्रोल रहता है और एक वह है कि जिसके द्वारा कार्पोरेशन इत्यादि का कंट्रोल रहता है । हर एक चीज में चाहे वह किसी भी प्रकार की हो भलाई के साथ कुछ न कुछ बुराई अवश्य रहती है । उसी प्रकार जब हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो उस में भी हम देखते हैं कि कुछ बुराइयां आ जाती हैं । मसलन जो चीजें डाइरेक्ट मिनिस्टर द्वारा कंट्रोल होती हैं और आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसरों द्वारा जिन की व्यवस्था होती है, उनमें भी हम यह देखते हैं कि हमारे अधिकारी चाहे वह बहुत निपुण हैं, कार्य-कुशल हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन उनमें एक सब से बड़ा डिफैक्ट यह रहता है कि उन्हों ने गत वर्षों में जिस एटमासफियर में, जिस वातावरण में काम किया है वह इस प्रकार का रहा है जिस से उन में ऐसे कार्य करने की जैसी क्षमता चाहिये वैसी नहीं पाई जाती है । दूसरी ओर जहां हम कारपोरेशन को लेते हैं वहां हम यह देखते हैं कि हम कंसालिडेटेड फंड द्वारा उन को आर्थिक सहायता देते है, लेकिन उन पर आडिटर जनरल का जो अधिकार है वह नहीं रहता । इसी वजह से अक्सर उन में

[श्री राम सहाय]

कुछ गड़बड़ियां देखने में आती हैं । राष्ट्रीयकरण के बारे में मिनिस्टर चर्चिल ने सन् १९४९, ५० में जो कहा था वह भी मैं विचारार्थ सदन के सामने रख देना मुनासिब ख्याल करता हूं । वह इस प्रकार है :

"Nationalised industries are monopolies in the worst sense of the word. If a private business should become a monopoly and abuse its position, there is no difficulty in dealing with it. But a government monopoly has behind it the whole strength of the government and under a socialist government the Ministers themselves have a political interest in trying to bolster it up so as to justify their own policy and conduct."

इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी बात हम प्रारम्भ करें, उस में कुछ न कुछ दिक्कतें अवश्य हमारे सामने रहती हैं । इंगलैंड में जब एटली की हुकूमत हुई तो उन्हों ने भी राष्ट्रीयकरण किया और उस राष्ट्रीयकरण में उन्हों ने खास तौर पर कोल, ट्रांस्पोर्ट, गैस, लोहा और इस्पात के बारे में सन् १९४६, ४७, ४८ और ४९ में कानून बनाये ।

इस तरह जब हम दूसरे देशों के इतिहास पर विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि सारे देशों में एक प्रकार की पद्धति नहीं है । हम रूस में देखते हैं कि वहां एक प्रकार से सभी उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है । वहां एक नाई की दूकान, बार्बर शाप, का भी राष्ट्रीयकरण है या उस धन्धे का भी राष्ट्रीयकरण किया हुआ है । अगर हम अमेरीका की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम यह देखते हैं कि वहां पबलिक युटिलिटीज के जो धन्धे हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइन्स, पावर जनरेटर, ब्राडकास्टिंग वगैरह, वे भी प्राइवेट लोग कर रहे हैं । ऐसी मिसाल दूसरे देशों में बहुत कम नजर आयेगी जैसी कि वहां देखने में आती है ।

किन्तु हमारी सरकार ने इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए जो पालिसी अख्तियार की है वह निश्चय ही ठीक है । वैसे तो जब हम किसी उद्योग या धन्धे का राष्ट्रीयकरण करने जाते हैं तो हमें चार बातें खास तौर पर अपने ध्यान में रखनी होती हैं । एक तो हम यह देखते हैं कि क्या किसी प्राइवेट उद्योग को कोई सहायता देनी है । हम इस बात को भी देखते हैं कि आर्थिक सहायता अगर न भी देनी हो, आर्थिक लाभ भी अगर न हो, तो भी सोशल्ली अगर उस की आवश्यकता है तो हम उस का राष्ट्रीयकरण करते हैं । इस के अलावा जब हम यह देखते हैं कि कोई प्राइवेट उद्योग या धन्धा ठीक तरीके पर संतोषप्रद नहीं चल रहा है तो भी हम उस का राष्ट्रीयकरण करते हैं । और चौथी बात यह है कि जब सरकार को किसी विशेष चीज की आवश्यकता होती है, किसी विशेष बात की आवश्यकता होती है, तो वह स्वयं उस का राष्ट्रीयकरण करती है । इस प्रकार से हम इन चार तरीकों के आधार पर ही आम तौर पर राष्ट्रीयकरण करने की बात सोचते हैं ।

भारत सरकार की जो इंडस्ट्रियल पालिसी है जिस की कि उस ने ३० अप्रैल, १९५६ को घोषणा की है उस के द्वारा उन्हों ने तीन हिस्सों में उस को तकसीम किया है । पहले हिस्से में वे अंडरटेकिंग्स हैं जो कि पूर्णतया या एक्सक्लुसिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, दूसरे में वे जिन में कि गवर्नमेंट की मिल्कियत तो होती है लेकिन उन में प्राइवेट लोगों का भी हाथ रहता है यानी वे इस प्रकार से मिश्रित रहते हैं, तीसरे में वे जो कि बिल्कुल प्राइवेटली ही चलती हैं । इस प्रकार से भारत सरकार ने संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी कांस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हवाला देते हुए जो नीति निर्धारित की है उस के कुछ थोड़े से कोटेशंस मैं हाउस के सामने, हाउस को रिमाइंड करने के लिये, पढ़ देना चाहता हूं । जैसा कि मैंने निवेदन किया, कांस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स का

हवाला देते हुए जो बातें उन्हों ने निश्चित की हैं वे इस प्रकार हैं :

"These basic and general principles were given a more precise direction when Parliament accepted in December, 1954, the socialist pattern of society as the objective of social and economic policy. Industrial policy, as other policies, must therefore be governed by these principles and directions. In order to realize this objective, it is essential to accelerate the rate of economic growth and to speed up industrialisation and in particular, to develop heavy industries and machine making industries, to expand the public sector, and to build up a large and growing co-operative sector. These provide the economic foundations for increasing opportunities for gainful employment and improving living standards and working conditions for the mass of the people. Equally, it is urgent, to reduce disparities in income and wealth which exist today, to prevent private monopolies and the concentration of economic power in different fields in the hands of small numbers of individuals. Accordingly, the State will progressively assume a predominant and direct responsibility for setting up new industrial undertakings and for developing transport facilities. It will also undertake State trading on an increasing scale. At the same time, as an agency for planned national development, in the context of the country's expanding economy, the private sector will have the opportunity to develop and expand. The principle of co-operation should be applied wherever possible and a steadily increasing proportion of the activities of the private sector developed along co-operative lines.

The adoption of the socialist pattern of society as the national objective, as well as the need for planned and rapid development, require that all industries of basic and strategic importance, or in the nature of public utility services, should be in the public sector. Other industries which are essential and require investment on a scale which only the State, in present circumstances, could provide, have also to be in the public sector."

यह जो मैं ने पढ़ कर सुनाया, इस से मेरी गर्ज यह है कि हम यह विचार करें कि दरअस्ल शासन ने जो अपनी नीति घोषित की है उस नीति से देश को लाभ हो रहा है या नहीं। जैसा कि मैं ने ऊपर जिक्र किया था उन्हों ने चार बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पालिसी बताई है वह देश के हित की दृष्टि से बहुत अच्छी है और इस से इस को लाभ भी काफी हुआ है लेकिन अस्ल में हमें देखना यह है कि इस वक्त जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से कार्य चल रहा है अथवा नहीं। इस में तो कोई शुबहा नहीं है कि इस पालिसी के द्वारा राष्ट्रीयकरण की ओर और देश की आर्थिक व्यवस्था की ओर हमारी सरकार का बहुत काफ़ी ध्यान है। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रपति जी ने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी उस का काफी विश्लेषण किया है। साथ ही कांग्रेस का अभी नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उस में भी योजना का जो प्रस्ताव था उस पर इन सब बातों की काफी चर्चा की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में जो कुछ कार्य हो रहा है वह संतोषजनक अवश्य है, इस में संदेह नहीं, लेकिन, जैसा कि मैं ने ऊपर जिक्र किया था, बाज बाज वक्त कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिन से कि लोगों के दिलों में कुछ शंकायें होती हैं, जैसे कि अभी फूडग्रेन्स की पालिसी के सम्बन्ध में सरकार ने यह निश्चय किया कि सारे गल्ले की खरीद फरोख्त सरकार द्वारा की जायेगी। इस प्रकार की विचारधारा या इस प्रकार की घोषणा प्रदर्शित तो कर दी गई लेकिन उस के बारे में जो प्रारम्भिक बातें थीं वे मेरे ख्याल से नहीं की गई। मैं समझता हूं कि पहले स्टेट गवर्नमेंट्स से--जिन के कि अधिकार की वह चीज है या जिन के द्वारा बतौर एजेंसी --कार्य कराया जाना है--इस बारे में मश्विरा अवश्य लेना चाहिये था और उन से

[राम सहाय]

मशविरा लेने के बाद ही इस प्रकार का कार्य होता तो निश्चय ही उस कार्य को करने में हमें देर भी नहीं होती और जैसी सफलता चाहिये थी वैसी सफलता भी हम को मिलती लेकिन इस एक छोटी सी बात के न होने से वह सारी स्कीम ही इस वक्त झमेले में पड़ गई है और हम देखते हैं कि प्रदेशों के जो बहुत से हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वे या तो मजबूर हैं या वे किसी कारण से पूरा सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्हीं ख्यालात से मुत्तासिर हो कर, इन्हीं ख्यालात से प्रभावित हो कर मैंने यह रेजोल्यूशन रखा है जिस से कि यदि गवर्नमेंट की नीति एक बहुत लम्बे अर्से के लिये बिल्कुल स्पष्टतः तय हो जाय तो लोगों को विचार करने में, सोचने में और कार्य करने में सहूलियत हो।

आप देखें कि गल्ले की खरीद फरोख्त का जो निर्णय अभी सरकार ने किया है उस की वजह से बहुत उथलपुथल हुई है और जो लोग इस प्रकार का धंधा करते थे वे तो उस की मुखालिफत इसलिये करते ही हैं कि वे यह समझते हैं कि उन का धंधा उन के हाथ से जा रहा है लेकिन जनता को पिछले जमाने का जो अनुभव है उस से जनता भी शंकित है इस बारे में कि हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वह इस कार्य को सुचारु रूप से चला पायेगी अथवा नहीं। हम देखते हैं कि जो मौजूदा मशीनरी है वह निश्चय ही इस प्रकार के खरीद फरोख्त के कार्य को करने में एक प्रकार से असमर्थ है और मेरा तो यह विश्वास है कि जब तक इस बारे में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये जायेंगे और हमारे देश के लोगों को उस प्रकार के वातावरण में उस प्रकार के एटमासफेयर में रहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा और साथ ही उस प्रकार की ट्रेनिंग उन को नहीं मिलेगी तब तक मैं समझता हूं कि वे इस प्रकार के कार्य करने के क्षम्य नहीं हो सकते हैं। मेरा यह अनुभव है कि पिछले दिनों में जब कुछ खरीद फरोख्त सरकार के द्वारा की गई थी—वह कुछ ही अंशों में की गई थी—तब उस में इतने घुटाले हुए हैं कि पांच वर्ष के बाद भी एक रोज ट्रेन में एक ऐसी पार्टी से मेरी भेंट हुई जो कि पांच वर्ष पहले का एकाउंट्स आडिट करने जा रही थी। उन से मेरी बातचीत हुई तो उन्हों ने यह बताया कि इस प्रकार की कुछ गड़बड़ियां हैं कि जिस से उन को सारे एकाउन्ट्स बराबर नहीं मिल पा रहे है। और मेरा भी अनुभव यह है कि उस वक्त जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की गई उस में बहुत सी उलझनें पैदा हुई और उस में काफी नुकस न महज अव्यवस्था के कारण ही हुआ। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हम किसी भी धंधे का राष्ट्रीयकरण करें, उस में किसी को कोई आशंका नहीं हो सकती और न होनी चाहिये क्योंकि दरअस्ल जनहित उस में निहित रहता है। लेकिन किसी भी धंधे का राष्ट्रीयकरण करने से पहले उस के प्रॉस एंड कॉंस को, उस के पक्ष और विपक्ष की बात को अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिये और इस की पूरी स्कीम हमारे पास तैयार होनी चाहिये कि किस प्रकार से और किन व्यक्तियों द्वारा उसे हम कार्यान्वित कर सकेंगे। इस का पूरा लेखा हमारे पास होना चाहिये। जब तक इस प्रकार का लेखा नहीं तैयार किया जायेगा या इस प्रकार का निश्चय नहीं किया जायेगा तब तक किसी कार्य में सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने इन सब बातों में काफी उन्नति की है, उन को उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुछ एक उद्योग धंधों की चर्चा करूं जिन का कि राष्ट्रीयकरण हुआ है तो कुछ बेजा नहीं। हमने देखा कि हमारे जो भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला में कारखाने हैं उन में दो कारखानों यानी भिलाई और रूरकेला में जो कार्य शुरू हुआ है वह बहुत ही अच्छा है। हमने देखा कि जैसे ही उस कारखाने का उत्पादन शुरू हुआ बाजार में लोहे का भाव गिर गया। निश्चय ही सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य होने से, जो दूसरे लोग इस प्रकार का कार्य

करते हैं उन को भी उस से यह सोचना पड़ता है कि वे किस प्रकार अपने व्यापार को चलायें। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी जो बंगलौर में है उस में जहां १९६१ तक ३१ मशीनें प्रति मास तैयार करने की व्यवस्था पहले सोची गयी थी वहां जनवरी १९५९ से ही १०० मशीनें तैयार होने लग गई हैं। पेनिसिलीन फैक्टरी, पिंपरी को अगर हम देखें तो जहां ६ मिलियन मेगा यूनिट पेनिसिलीन तैयार करने का टार्गेट मुकर्रर किया गया था वहां हम ३४ मिलियन मेगा यूनिट तैयार करने लगे हैं, और सब से बड़ी विशेषता इस में जो हुई है वह यह हुई है कि उस कारखाने की कैपेसिटी केवल २४ मिलियन मेगा यूनिट तैयार करने की थी लेकिन हमारे देश के जो विद्वान और कुशल लोग वहां कार्य कर रहे थे उन्होंने वहां की मशीन की जो कार्य करने की कैपेसिटी थी उस को २४ से ३४ तक बढ़ा लिया। यह एक बहुत ही सराहनीय बात है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो देहली की जो डी० डी० टी० की फैक्टरी है उस में भी १४०० टन डी० डी० टी० तैयार हो रही है। सिन्दरी फैक्टरी को अगर हम देखें तो वहां १००० टन प्रति दिन हम खाद तैयार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहां जो कार्य चल रहे हैं और उस में जो लोग काम कर रहे हैं उस में हमें कोई त्रुटि नहीं मालूम होती, सिर्फ उस प्रकार के वातावरण का, उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा का ही प्रश्न हमारे सामने रहता है। हमारी आर्डनेन्स फैक्टरी में भी जो कार्य हो रहा है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एटामिक एनर्जी का भी जो कार्य हो रहा है वह भी सराहनीय है। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल पालिसी घोषित की गई है और उस के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह निश्चय ही बहुत अच्छा है इस में मुझे अधिक कहने की गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत त्रुटि सामने नजर आती है उस के सम्बन्ध में मैंने यह सोचा कि इस प्रकार का प्रस्ताव रख कर अगर उसके द्वारा कार्य किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। जिस प्रकार की कमेटी का उल्लेख मैं ने अपने प्रस्ताव में किया है उस में विशेषता यह रहती है कि जहां हम विशेषज्ञों का मशविरा तो लेते ही हैं—वैसे तो गवर्नमेंट अपनी पालिसी निर्धारित करने के लिये सदैव ही विशेषज्ञों का मशिवरा लेती है, इस में सन्देह नहीं—वहां उस में हमारे अपोजीशन के मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता है और उन का दृष्टिकोण भी हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारे सामने आने से या इस प्रकार का सहयोग हमें मिलने से उस में बाद को कम से कम क्रिटिसिज्म की गुंजाइश रह पाती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा तो निश्चय ही हमारी सरकार के लिये यह एक अच्छी चीज होगी और भविष्य के लिये लोगों में जो एक प्रकार की शंका और कुशंका के अवसर प्राप्त होते हैं वे भी दूर हो जायेंगे।

मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और एक बार फिर यह नम्र निवेदन करूंगा और मिनिस्टर महोदय से भी इस बारे में निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और विचार कर के देखें। अगर उन को यह मालूम हो कि दरअसल जनहित की दृष्टि से और कम से कम इस दृष्टि से कि शासन को कम से कम क्रिटिसिज्म का अवसर प्राप्त हो, अगर वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House is of opinion that Government should appoint a Committee consisting of Members of Parliament and persons having expert knowledge of the subject to consider and make recommendations as to the trades and industries which should be nationalised having regard to the present situation in the country."

[Mr. Chairman.]

Every subsequent Member has 15 minutes' time, except the Minister concerned who may take half an hour.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Chairman, I am grateful to the hon. Member for giving us an opportunity to speak on a very important subject, the importance of which is all the more today in view of certain economic trends and developments in our country. It is also important because we are discussing this matter after the Nagpur session of the Congress, where certain fine sentiments were expressed in favour of developing the public sector. I should begin by a reference to the Industrial Policy Resolution of the Government in which it is stated:—

> "In order to realise this objective, it is essential to accelerate the rate of economic growth and to speed up industrialisation and, in particular, to develop heavy industries and machine making industries, to expand the public sector, and to build up a large and growing co-operative sector."

Then, again, it goes on to say:—

> "The State has, therefore, to assume direct responsibility for the future development of industries over a wider area."

The emphasis was definitely laid on the public sector, though somewhat haltingly, as is often the case with the Government there.

Then, Sir, you will remember the Prime Minister was very fond of once talking about strategic heights in our economy. Three or four years ago in this House and the other House we were told that, although a general policy of nationalisation would not be followed in this country with regard to important industries, strategic heights in our country would have to be captured. I would ask the Field-Marshals of the Congress Party to what extent the capture has been achieved. As far as I can see, the strategic heights remain in possession of the big business and we are being constantly sniped at from those heights. We talk, we speak, we issue sermons, we express sentiments, but these people go on at the top. Now, Sir, the Nagpur session was spelling out certain fine sentiments about the public sector, still trying to develop a sector of that kind. Another gentleman, that is to say, the Chairman of the Reserve Bank of India, Mr. Iengar, was making a speech in Bombay where he pointed out how the private sector was getting on well and issued certificates to the private sector.

My friends opposite who are connected with business will bear me out that these certificates relate to the monopolist elements in the private sector, not to the small fries. That is how there is this contradiction which exists between professed sentiment and practice and that is how the political platform of the organisation stands in sharp contradistinction to the policy platform of the Government as embodied in such institutions as the Reserve Bank. Make your choice for good. Sentiments are there and they have to be translated into policies and once they are translated into policies, they have to be implemented. We would like to hear what Mr. Chinai has to say and what the Minister has to say in reply. It appears that Nagpur was not missing the advantage of hearing Mr. Chinai who raised the cry of big business there in order to silence even the faint voice that was raised there for developing the public sector. Now, I understand that the Congress House is a very mixed house just as their mixed economy and naturally Mr. Chinai goes hand in hand with others.

Let us now, Sir, come to the question about the strategic heights. As I said, the heights are still in possession of the big business. The coal industry is in the hands of the big business, especially foreign; banking remains largely in the hands of the big business; engineering remains largely in foreign hands. Cement and all the vital industries are today in the hands of the monopolists and it is they who con-

trol such industries. In that context, naturally the question of nationalisation becomes one of very great importance.

We talk about difficulties in regard to resources for the Five Year Plans. We are in the midst of a crisis. At the same time we find that the profit-yielding undertakings in the country, whether in the banking industry or the coal-mining industry or the tea industry or in the jute industry, are in the hands of monopolist elements. What is the use of bemoaning our fate and crying over lack of resources when we see before our eyes the private sector elements making profits never before and building up their structures of economy in a manner menacing to the entire country? What is the use of talking about taxation and austerity as far as the people are concerned, when I find the millionaires becoming multi-millionaires and profits soaring so high that they have to cart out money abroad and put it in different banks? In the other House yesterday, we were told that about Rs. 62 crores of Indian undertakings are there in the foreign banks. We were also told by the Finance Minister that to have bank accounts abroad without the permission of the Reserve Bank would constitute a criminal offence. I would like to ask them why such people are not being tried for criminal offences. On the contrary, it seems that they get on very well.

* * * *

MR. CHAIRMAN: Order, order.

SHRI BHUPESH GUPTA: Now, Sir, I come to the other points. I do not know how you will expand the public sector if you do not adopt a vigorous policy of nationalisation. Can we build up a strong and powerful public sector merely by starting some new undertakings and industries much as important as they are? Therefore, it is essential for the expansion of the public sector to implement the policy of nationalisation and wherever it is essential and necessary, we must adopt it. I am grateful to the hon. Member for having given us this opportunity to raise this issue. We are told that resources have to be found for the public sector. It is very good and we welcome that particular declaration of the Nagpur session of the Congress because we are not allergic to good things when they come from that quarter even though the other side would not touch things as long as they do not come from its own side. I say, Sir, implement it and implement it by nationalising certain undertakings. In order to find resources for the Plan, we will have to carry out a policy of nationalisation so that the profits earned by these undertakings would accrue to the Government, when they come over to the State sector, for being used in the industrial development of the country and directed into planned channels of development and economy.

Finally, Sir, take another factor, the British concerns that dominate the Indian scene today. Today about Rs. 600 crores worth of foreign capital is invested in the private sector of which 85 per cent. or 90 per cent. would be accounted for by the British. This figure was a little over Rs. 300 crores in 1948 and today it stands at about Rs. 600 crores. This is how this process is going on here whereas in Indonesia complete nationalisation has been carried out in respect of the foreign Dutch holdings and investments. Now, the process adopted by our Government is not a very helpful process for our economic development or for the development of the public sector. The foreign concerns work to the detriment of our national economy. Take, for instance, the coal industry. Britishers control 60 per cent. of the total coal production in the country and the entire best grade coal and metallurgical coal mines are exclusively controlled by them. There are concerns like Andrew Yule & Co., McNeil & Brady, Turner Morrison, Shaw Wallace & Co., the Assam Trading Corporation, etc., and these concerns control nearly 95 per cent. of the coal industry which is under British management. I would ask the

***Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Bhupesh Gupta.]

hon. Minister to note that Andrew Yule & Co. produces more coal than the entire State sector. That is the state of affairs. You can understand their grip on the industry from this single fact. They declare dividends ranging from 16 per cent. to 40 per cent., sometimes even 50 per cent. and their profits are going up. They get in addition price increases also. The Indian National Trade Union Congress and the All-India Trade Union Congress have repeatedly drawn the attention of the Government to the high profits and the reckless manner in which these concerns carry on their mining operations. They are reckless and slaughter mining and these mines have become death pits to our workers, slaughtering our workers and the indentured Gorakhpur labour. Last year we had a very grim tragedy in the Chinakuri coal mine controlled by the Bengal Coal Company owned by Andrew Yule & Co. As you know, Sir, there the figure would be no less than 300 killed. An enquiry was held, a farcical enquiry. One of the Mohicans of the Indian Civil Service was discovered to undertake the enquiry there. The enquiry was conducted in such a manner as to deplete the figure of death to 176. The plan submitted by the Bengal Coal Company—I always give documentary proof—shows that there were more than 13 dead bodies without the skull as against six shown in the Enquiry Committee's Report, double. Even the plan submitted by the Bengal Coal Co. was not taken into account when giving the findings. This is the difference in regard to one section; if the other sections are taken into account, the number will easily be more than 300 killed as against the 176 shown in the Enquiry Committee's Report. Hon. Members should kindly study such things. I am surprised that Government do not stop such things, this kind of reckless mining. The foreign owners operate the mines not only in a reckless manner for earning profits out of the sweat and toil of our masses but they operate the mines in such a manner that this kind of accidents happen. Sir, safety regulations and rules for safety are never adhered to and yet they get on fine with our Mining Department. I do not know why such things happen. I also do not know what golden bonds bind our Mining Department of the Government with the British coal mine owners in India but there is something. We want this to be brought into the public sector, I mean the coal industry, so that we may discuss in Parliament such matters and call these people to account. It is essential therefore, even in the interest of running our coal mines according to the best interests of the country in keeping with the safety regulations and mining rules, that such a vital industry in our country should be placed in the hands of the nation. Now, the attendance register was not there in Chinakuri. I do not know; well, the I.C.S. officer who is an old gentleman, maybe, was sleeping or some such thing. He missed everything; missed even this particular map produced before the court and much of the evidence was taken after the workers had given their evidence. And how it was done is a very interesting matter. Sir, I should like to point out only one thing in this connection. When the enquiry took place the workers' representatives gave evidence—the representatives of the Federation. After the evidence of the Federation had been taken, suddenly in August they started taking the evidence of the management. Sir, here is the booklet. It is said: "After the argument of the workers' representatives was over on the 28th August . . . "

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar): I want to know just one thing. Where is the relevance of all this to the Resolution before us?

SHRI BHUPESH GUPTA: The hon. Member has long been in Supreme Court but I am sorry that he does not understand the relevance of it. The relevance is that if you leave these things in the private sector, they not only kill the workers but they

corrupt your departments that even enquiries become a mockery. That is the reason why I am stating this fact.

SHRI D. A. MIRZA (Madras): Why is the hon. Member agitated so much?

MR. CHAIRMAN: It is not for you to say that.

SHRI BHUPESH GUPTA: I do not know; the hon. *ex*-Prince will perhaps not understand how the millowners in the coal mining industry . . .

MR. CHAIRMAN: Order, order.

SHRI BHUPESH GUPTA: So this is how they go on. There is the banking industry; there is the electrical industry. Rs. 1,600 crores are in their hands. Part of it is in the hands of the State Bank but the rest of it is in the hands of Scheduled Banks and the money is utilised for building up the private sector and not for development of the economy as it should be. Then there is the cement industry in our country.

MR. CHAIRMAN: It is time. You cannot have more time.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am just finishing, Sir. About 70 to 75 per cent. of the cement is bought by the public sector but the industry is in the hands of the private sector. Similarly, tea, Calcutta Tramways, Electricity etc. What I suggest therefore is that the matter should be considered and it is essential that as far as coal mining is concerned, we should take over the entire coal mines. And in this particular case we should order a re-enquiry. There should be a fresh enquiry and all these people, including Mr. Whitaker, who controls everything there, should be removed. This industry should be taken over. Sir, finally one thing. I have brought this point to your notice. I would beg of the Government to consider this matter—this booklet is there—and see if there is a *prima facie* case for starting a fresh enquiry and remove Mr. Whitaker who is the head of the Department, who certifies the plants, equipments and other things.

SHRI M. C. SHAH (Bombay): Mr. Chairman, Sir, I am afraid . . .

MR. CHAIRMAN: You are afraid of your predecessor?

SHRI M. C. SHAH: I am afraid the acceptance of this Resolution by the House will perhaps unnecessarily embarrass the Government in the formulation of the third Plan. The only effect of this Resolution will be to create unnecessary panic in the economy of the country. We have already accepted that we should have a planned economy and whenever necessary the Government comes forward with proposals for nationalisation when they think it is in the best interests of the country. Sir, we have accepted the position that there will exist both the public sector and the private sector. They are complementary or supplementary to each other and now to have a committee of experts and Members of Parliament to find out which trades and industries should be nationalised will certainly create, as I said just now, unnecessary panic in the private sector or in the industry. Sir, I do not understand the desirability of nationalising those trades and industries which are doing well. In the interests of the country of course there should be control and for that we already have the Companies Act, and the Industries (Regulation and Development) Act to control the working of those industries. For example so many times it has been suggested by some prominent Members here that the textile industry should be nationalised. What is the good of investing crores of rupees in the industry that is already established there for a number of years, when we have our hands full with the implementation of new schemes? We have already decided to set up heavy industries, machine-making industries and industries which cannot be set up in the private sector and we are well advanced on that scheme. Now, unless we consolidate all those that we have undertaken and all those that we propose to undertake in the

[Shri M. C. Shah.]

third Plan, it is no use advocating the nationalisation of existing trades and industries. Our enthusiasm should not outrun our ability. Have we got the resources? Already we have seen the strains and stresses in the execution of the second Plan. The third year was a very critical period. What was the position of our external resources and what was the position of our internal resources? We had to go to foreign countries and ask them to come to our aid in order that the requirements of the second Five Year Plan's external resources could be met. We are grateful to those countries that have given us help to the extent of 360 million dollars. For the next two years we are again negotiating loans for nearly 700 million dollars which will be required for the implementation of the second Plan—a Plan worth Rs. 4,500 crores which really speaking, according to the prices prevailing when the Plan was framed, would have cost only Rs. 3,600 or Rs. 3,700 crores. We have also difficulties about internal resources. We could not get enough loans and we have fallen short in small savings. We have to husband all our resources in order to implement the schemes for heavy industries, machine-making industries and such other basic industries. Instead of that if we fritter away the resources that are available to us—and they are very scarce—in just nationalising the trades and industries that are already being run today, I think that it will not be a wise step. Really speaking we will be out-Heroding Herod. The most progressive person about all these things is our Prime Minister and the Prime Minister has so often said that it is no use nationalising those industries which are running or those that have old machinery and which are outmoded and are to be modernised. Now we have a resolution that we must nationalise the trades. We have already decided about State trading in foodgrains. We have no apparatus, we have no machinery, we have created a scare in the country, and the prices have gone up. So, I think it is not advisable to pass a resolution of this type at this stage. We are not helping the cause of the country. We are not helping by adopting this resolution our position, because whatever is necessary will be done when the Third Plan in formulated.

Sir, I was one of those who had a part to play in the nationalisation of life insurance. So I am not against nationalisation whenever it is necessary and whenever it is in the best interests of the country. We must nationalise public utility services as we have nationalised life insurance. But unfortunately, after that Mundhra affair, my faith in the working of nationalised companies was almost then shaken. Have we got the administrative machinery competent and adequate enough to manage all those things? We are told, it is reported and possibly it is not contradicted, that when we just establish these huge undertakings, the expenditure will be more. It is said that we are standing an expenditure more than what a prudent person will stand, maybe because of certain factors and certain circumstances, but our administrative machinery—I may be pardoned for saying this—is almost creaking. We have not got enough personnel to manage all these affairs, so that it is always better to manage what we have already undertaken and also undertake just those new things which are absolutely necessary instead of frittering away our resources and energies in trying to nationalise the industries that are existing today. Of course if any of those industries is working against the interests of the nation, then you certainly nationalise that industry. You single out that industry and make out a clear case for nationalisation of that industry, and I think nobody will object to the nationalisation of that industry immediately even though it will be difficult to find the resources, even though it will be difficult to find an adequate administrative machinery. But this resolution asks generally to find out which trades should be nationalised or which

industries should be nationalised. I think it is not a desirable resolution. I do not know the attitude of the Government, but I think the Government will be well advised to oppose such a resolution.

SHRI H. P. SAKSENA (Uttar Pradesh): Was not the hon. Member responsible for the nationalisation of the Imperial Bank?

SHRI M. C. SHAH: I was associated with that measure of nationalisation of the Imperial Bank. I am proud that I was associated with that measure, and I say that it was absolutely necessary. I maintain that whenever it is absolutely necessary to nationalise an industry in the national interests, one should not hestitate for a moment in doing that. You find out that industry, show that it is acting against the interests of the nation and then go in for the nationalisation of that industry. But just to say that you find out what trades should be nationalised or what industries should be nationalised is in my opinion not worth taking all the trouble.

MR. CHAIRMAN: Mr. Shah, address the Chair.

SHRI M. C. SHAH: I am sorry, Sir. What I say is that I am not against nationalisation whenever it is necessary, and I have done what I can in trying to nationalise certain things. Therefore, please do not misunderstand me when I say that this resolution today is inopportune. I do not say that industries should not be nationalised. But if we accept this resolution, we will be playing into the hands of my friends like Shri Bhupesh Gupta. (*Interruptions.*) If I were a wise man, I should not like to be caught in the trap of my friend Mr. Bhupesh Gupta who would like to have everything nationalised and everything taken over by Government.

SHRI BHUPESH GUPTA: I have not got such a trap or net to catch such a big fish.

SHRI M. C. SHAH: So, Sir, while accepting the principle of nationalising whatever industry or whatever trade is found to be absolutely in the national interest, I say that such a resolution should not be accepted.

Today we find that not only we want foreign assistance on a Government to Government basis but we also need foreign equity capital in this country in order to establish new industries or expand the existing industries. Therefore we should not create an unfavourable climate by saying that we will nationalise anything and everything that we like. I think that will deter the flow of foreign equity capital into this country which is absolutely necessary in order to develop our country, in order to industrialise our country as fast as we can. Therefore, Sir, from that aspect also the resolution today is premature and I do not think it is advisable to accept it at this moment.

Sir, the Planning Commission is trying to formulate the Third Five Year Plan. Experts are to be consulted. Panels will be appointed. In the framework of the Third Plan whatever is absolutely necessary will be there. It will take into account all our resources. So, in order that the Government may not be embarrassed, in order that the Planning Commission may not be embarrassed in the formulation of the Third Plan, we should not bind down their hands by the appointment of such a Committee for the nationalisation of this or that industry.

Thank you, Sir.

(*Shri Ahmad Said Khan stood up.*)

MR. CHAIRMAN: The infection is spreading. Everybody is getting excited. The Nawab of Chhatari.

SHRI AHMAD SAID KHAN (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, I thought when I read this resolution that it was rather an innocent proposal. But when I found that my friend, the

[Shri Ahmad Said Khan.]
leader of the opposition, supported it so vehemently and with such force, I thought that there must be something basically wrong with the resolution. I am certain, Sir, that the Mover himself by now must have been converted to the idea that this resolution should be opposed.

Sir, there is no real virtue either in an administration being nationalised or its being run by private management. The real virtue is how to increase production. That should be the purpose. Now let us see whether, if such a Committee is appointed, it will help in increasing production or it will not. I say, Sir, that if such a Committee is appointed, the result will be that capital will get shy. It will create uncertainly in the industrial world. We are in need of foreign capital to develop our industries. All that foreign capital will get shy, and the net result will be that our industrial progress will be very much hampered. If this resolution is adopted by the House, the Sword of Damocles will be hanging all the time over the necks of the industrialists. Capital will get shy and people will not like to invest their money in the industries. Sir, even the foremost socialists were of the opinion, even Karl Marx was of the opinion, that industrialisation should come first and nationalisation should follow industrialisation. Here we are very much backward in industry. We have not yet industrialised our country fully and if we appoint such a Committee, it will create great uncertainty in the minds of the industrialists. I am sure, Sir, that it will be wrong. Moreover, our policy so far has been one of mixed economy. All the big industries, all the big enterprises which the private sector has not got the means to develop we are having in the hands of the Government and we are doing it.

12 NOON

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

We know that we have not got enough technicians, enough people, to man the administration and the absence of private incentive is causing trouble in the development of the industries that have been nationalised. Therefore, it will be a good thing to keep to this mixed economy and not to appoint a committee which will be regarded by the industrialists as a sort of Damocles Sword over their heads. Moreover, I may say that, in my opinion, mixed economy can be run in this way also that in many concerns the Government may have control in shares, say, 40 or 35 per cent. and the rest of the shares should remain in the hands of the private sector. The advantage will be that the acumen and experience of the private sector will be at the disposal of the Government and control of the Government will be there so that there may be no monopoly. Otherwise, if this Resolution is accepted, I think it will have a very bad effect on the industrialists of our country and the Government should oppose this Resolution.

SHRI ROHIT M. DAVE (Bombay): Mr. Deputy Chairman, I have no hesitation in lending my full support to the Resolution which has been moved by the hon. Shri Ram Sahai. This Resolution is very timely and the Government will be well advised to take into consideration the various factors which the Mover has already enumerated in support of his Resolution.

Sir, as this House knows very well, the Government always has thought it necessary to come out with a statemtnt of policy regarding the control and planning of economy at the beginning of every Plan. The First Plan was preceded by the Industrial Policy Resolution of 1948 and when experience was gathered during the working of the First Plan, the Government thought it necessary to come out with another Resolution again on Industrial Policy in 1956 and at that time it was stated by the Government that that Resolution

had become necessary because of the experience that was gathered during the working of the First Plan. Similarly, we are now on the threshold of the Third Plan and it will be necessary for us to consider again the Industrial Policy of the Government in the light of the experience that we have gathered during the Second Plan period. It is true that the 1948 Resolution and the 1956 Resolution emanated from the Government and no Committee was appointed at that time to examine the various aspects of these Industrial policies. But we must also remember that the entire responsibility for the formulation of the First and Second Plans was taken by the Government itself. When we are on the threshold of the Third Plan, responsible Government spokesmen and even the President have expressed the desire that all the various elements of the nation should combine together at the very outset to apply their minds to the formulation of the Third Plan and that co-operation from all sections is welcome by the Government. When various sections of the community are trying to apply their minds to the problems of the Third Plan, it will be necessary for the country to know exactly what should be the industrial policy, what should be the economic policy, that should govern the formulation of the Third Plan. It is because of this that this particular problem should not be left to the Government alone, but all the various elements in the community should be associated with the exploration of this problem.

It may be argued that the 1956 Resolution is fairly clear and nothing has happened during the Second Plan period so far which requires any re-examination of this problem. I respectfully beg to differ from that position. Enough has happened during the Second Plan period even so far which might make it necessary that we should re-examine the 1956 Resolution. The Reserve Bank year after year has drawn attention to the fact that the savings of the community are not keeping pace with the requirements of the economy. We have been told even by Government spokesmen that one of the problems which creates great anxiety in the mind of the Planning Commission is this fact of the non-availability of even savings. Saving today is in the hands of the banking system and we have only the Reserve Bank and the State Bank which are nationalised. The other banks—and especially the foreign exchange banks—are still in private hands and it will be necessary to examine whether it is desirable that the other scheduled banks should also be nationalised or should be brought under more effective control of the Government if the savings drive is to be given impetus. The Mover of the Resolution has very wisely kept the thing quite open for the Committee to discuss all the issues.

It need not be taken for granted that merely because a Committee is appointed, that Committee would be biased in favour of nationalisation only. It will be necessary for it to examine all the pros and cons and to see whether the time has come for nationalising the entire credit system. This House and the other House have already discussed the L.I.C. investment policy, but the comments in these Houses as well as in the public make it quite clear that that investment policy also is still not quite clear. Will this investment policy lead to nationalisation by the back-door, will that policy ultimately lead to the control of the various industries by the Government or will it lead to a greater participation in the profits that the economy as a whole has created, are the problems which exercise the minds of the public. This Committee will have to go into that aspect also and evolve a consistent investment policy not only with reference to the L.I.C. funds, but also with reference to the other funds that are at the disposal of the Government and which can be utilised for productive purposes. Particularly, Sir, we have got a coal shortage in

[Shri Rohit M. Dave.]
the country. We find that the Second Plan exploitation regarding coal and other energies has not fully materialised. It will be necessary for this Committee to go into that question also and see whether nationalisation is the right course again. Again, the question is quite open. The Committee can as well come to the conclusion that nationalisation is not the solution, nationalisation is not the answer. But the Committee might equally come to the conclusion that nationalisation is an answer. All that I submit is that this question needs examination. And unless we are able to find out some solutions for the problems of power, for the problems of coal and electricity—the problems that we are facing—it will not be possible for us to evolve a Third Plan on a consistent and rationally scientific basis.

Then, Sir, there is the question of transport. The Railway Board and the Railway Minister themselves have time and again drawn the attention of the nation to the fact that the transport system is not adequate to look after the big productive potential that is generated in the economy. We have to find an answer to this question also. Is the nationalisation of Railways enough to give us that transport system which our economy demands, or is it necessary that road transport should also be nationalised and shipping also should be nationalised? Again the question is open. My submission only is that it needs to be discussed.

Sir, during the Second Plan period enough experience has been gathered, enough data has come to light. It has to be examined, it has to be analysed, and in the light of that examination, a fresh reconsideration of the Industrial Policy Resolution is to be attempted. It may be that at the end of these deliberations we might again come to the same conclusion, *viz.*, that the 1954 Resolution is adequate, or we might come to the conclusion that it is not adequate. Let us not bind down, let us not try to colour the consideration by the Committee of this problem of nationalisation. But this problem needs to be examined. And, if it needs to be examined, it needs to be examined by a body which is outside the Government because the Third Plan is going to be the responsibility of the nation as a whole. Therefore, it is necessary that those who can guide the nation as a whole are able to apply their minds to these problems and then come to certain conclusions.

One more point that this Committee will have to discuss will be the effect of any nationalisation on our industry, on the development of our industry. Sir, the case is made out that if large-scale industrialisation is attempted, foreign capital is likely to get shy and we may not get enough equity capital which is necessary for the development of our economy. We have been told by the President himself that whenever we get loans from outside countries, there are no political strings attached to them. I would like to know exactly what is the meaning of these "political strings"? Does it only mean that you need not be a member of this power bloc or that power bloc? Or, does it also mean that we are completely free to determine our own economic policy? If even by implication or indirectly it has been suggested that if we want foreign aid, if we want foreign equity capital, we will have to determine our economic and industrial policy to suit the investors from outside, then the whole question as to up to what extent we should depend upon foreign capital and foreign assistance for the development of our economy will have to be gone into. Again, the Committee might come to the conclusion that, well, we have to make the best of a bad bargain, that we are in a very unhappy position and it will not be possible for us to develop our economy unless we get capital from outside and directly or indirectly certain implications are involved in getting

that assistance from outside; let them come to that conclusion and let that conclusion be known to the country so that it may be possible for the country to decide as to whether this type of assistance is desirable or not.

Finally, Sir, there is the question of the impact of such a policy on the private sector itself. We have been told again and again that if the public sector expands, if greater nationalisation takes place, the private sector will dry up and enterprise will go away, initiative will disappear, capital formation which is taking place in the private sector today will not be available to the economy and thereby we will be going to a position where there will be stagnation. This question also needs to be examined, because unless we tell the country in quite clear terms what exactly is the nature of the democracy that we are envisaging, what type of freedom—political, economic and civic—that we are trying to give to this country, what is exactly involved in planning, what is exactly involved in regulation. what is exactly involved in nationalisation, unless categorical answers are given, this type of confusion will continue and the public mind will be under the pressure of propaganda from this side or from the other side; it will not be possible for the public to know exactly where it stands, where its freedom stands of which the public is so zealous and proud. It is for these reasons that the question needs a thorough examination and an expert opinion on the various aspects that are involved in nationalisation ought to be clearly formulated and placed before the country. Only such a Committee can do that and, therefore, it is very necessary that such a Committee should be appointed.

SHRI P. D. HIMATSINGKA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, I heard the Mover speaking on his Resolution, and I understood him to say that he has proposed this Resolution in order that the position that is created in the country from time to time by different statements from different sides may be clarified. He is not very anxious that the trade should be nationalised or any particular industry should be nationalised. He wants it to be made clear as to whether or not there is any scope for any nationalisation of any trade. At least that was the purport, as I understood him, of his speech. So far as that intention is concerned, as you know and as hon. Members who have preceded me have referred, there has been a clear declaration in the Industrial Policy Resolution of 30th April, 1956 dividing the industries into three categories. That Resolution makes the position of the Government quite clear. Sir, they have set out in Schedule A various industries which will be exclusively in the public sector. And if you look into the list containing 17 items, you will find that the resources that the Government have at their disposal will not at all be sufficient to meet the needs of those industries themselves. Then there is Schedule B about which it has been said:

> "The second category will consist of industries, which will be progressively State-owned and in which the State will, therefore, generally take the initiative in establishing new undertakings, but in which private enterprise will also be expected to supplement the effort of the State."

You will find, Sir, that almost all the minerals which are not covered by the Schedule A list—aluminium, machine tools, ferro alloys and tool steels, basic and intermediate products required by chemical industries such as the manufacture of drugs, dyestuffs and plastics, antibiotics and other essential drugs, fertilizers, synthetic rubber, carbonisation of coal, chemical pulp, road transport and sea transport—have been mentioned. As a matter of fact, they were mentioned by the hon. Member, Shri Bhupesh Gupta. So far as coal is concerned, as was mentioned by him. more coal than what the public sector needed had been manufactured.

[Shri P. D. Himatsingka.]

That may be quite true, but at the present moment, Sir, the Government have taken over this coal in the public sector, and they have taken over a number of coal-bearing fields from various private parties under the Act that was passed by Parliament two years ago. Therefore, Sir, the position at the present moment is that the Government have in their hands a number of industries for which the resources that they have are barely sufficient to carry on. Therefore, Sir, if you appoint a Committee consisting of Members of Parliament and certain other persons with expert knowledge to consider and make recommendations as to the trades and industries which should be nationalised, it will absolutely be a waste of time, energy and money. The policy is quite clear, and as a matter of fact, it will be some time before the Government can take up the work that they have already decided to undertake by the adoption of that Policy Resolution. And so far as trading also is concerned, as you know, Sir, the State Trading Corporation has been functioning for some time, and if you examine carefully what it has been doing, you will be able to find that the business that was being carried on by private parties has been taken over. Rather it has just intervened to take a big share of the profits of those private parties, because there is that monopoly in the matter of export of iron. The State Trading Corporation will export iron ore. But I do not actually know the amount that is being spent on the organisation of the State Trading Corporation, whether it is eating up any major portion of the profits that would accrue to it. Sir, export of manganese was going on very well before the State Trading Corporation took it over, and during the last two years, Sir, practically no manganese has been exported, because the State Trading Corporation has not been able to effect many sales.

SHRI J. V. K. VALLABHARAO (Andhra Pradesh): Is it because the State Trading Corporation has taken over the export of manganese or is it because of recession in the European market?

SHRI P. D. HIMATSINGKA: It is so partly because of recession and partly because the State Trading Corporation has taken it over. When private parties were in charge of exports, they used to take all possible steps to get in touch with the purchasers in different countries. They would not hesitate to go to them and make contracts with them. It may be, Sir, that so far as manganese is concerned, this may be one of the reasons, but competitors have also come into the market. Brazil and other countries have begun to supply manganese, and I think that one of the reasons why this export has fallen is that the State Trading Corporation cannot take such effective steps as were being taken by those private parties. That appears to be one of the reasons why exports have fallen. What I want to submit, Sir, is that the Government has not got enough resources in its hands, and if we increase the scope of work, there is bound to be confusion and loss, which will not be noticed for some time before the mischief is done.

At the present moment, Sir, we have been hearing a lot about State trading in foodgrains. I do not know whether all the important persons in the Government who have been speaking in connection with State trading in foodgrains mean the same thing as is understood by the hon. Prime Minister, the Food Minister and others. As a matter of fact, Sir, confusion has been created in the different States, and they do not know whether State trading should be from top to bottom, and they do not know from what stage to what stage State trading in foodgrains should be undertaken. Certain statements are made from time to time without actually formulating the proposition in a clear-cut manner as to what exactly is to be done. That creates confusion in the country. As a matter of fact, Sir, I understand that in U.P. and other places, rice has been selling at about 27 rupees and wheat at about 32 rupees. The same thing

is happening in Punjab, because certain proper steps have not been taken by the Government. Therefore, Sir, before we start any new proposition, we should consider all its pros and cons and take proper steps to see that what we intend to do is really achieved. But unfortunately that is not being done.

Let us look at our resources. As you know, Sir, even at the present moment the resources that we need for our Second Five Year Plan are not sufficient. We need about Rs. 400 crores more to carry out only the core of the Plan. But if we want to implement all the items in the Plan, we will need more and more money. If we take into consideration our physical targets, there will be more and more shortage because the prices of almost all items have gone up, and we will have to make up in the next two years. But with the amount of taxation that has already been levied, I do not think that there is much room for raising more money to make up this deficit. Already the Third Five Year Plan is in the offing, which will require more and more money, and it will be so difficult to collect that money. Therefore, Sir, we should be very careful before we expand our activities, so that we may not spoil what we have already started. We should consolidate whatever has been taken up, and we should try to increase our national income, which can be applied for other purposes in order to help the economic growth of the country. The Resolution, as it stands, in harmless but it has been pointed out by some of the previous speakers, it will raise various questions in the mind of the public and will simply create difficulties. I would, therefore, suggest that this Resolution should not be pressed.

डा० जेड० ए० अहमद (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का, जो माननीय राम सहाय जी ने पेश किया है, समर्थन करता हूं । मुझे ताज्जुब होता है कि इस प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई और

कुछ इसके हक में हैं और कुछ इसके खिलाफ़ हैं । मैं समझता हूं कि ऐसे प्रस्ताव को हमें एकमत से मान लेना चाहिये था । चूंकि एक सवाल हमारे सामने है—हमारे दोस्त यह कहते हैं—कि बहुत से उलझाव हैं, बहुत से कंफ्युजन हैं, तो अगर कंफ्युजन है तो उसे साफ करना जरूरी है और अगर उसको साफ करना चाहते हैं तो फिर एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि आप ऐसे जिम्मेदार लोगों की समिति बनायें जिन्हें कि जानकारी है, जो कि मुल्क की राजनीति जानते हैं और मुल्क की समस्याओं को पहचानते हैं और वे इसके ऊपर अपनी राय दें. . . .

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका : . . . और उलझनें बढ़ाये ।

डा० जेड० ए० अहमद : जी हां, आपको अंदेशा यह है कि मुमकिन है कि उनकी सिफारिशें ऐसी हों जो कि आपकी विचारधारा के खिलाफ जांय । एक, दो आनरेबिल स्पीकर्स को मैंने सुना और मैंने देखा कि उन्हें डर मालूम देता है कि कहीं स्टेट सैक्टर और नैशनलाइजेशन बढ़ न जाय । यह अंदेशा आपको दिखाई देता है । अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा । अगर जिन्दगी का यह तकाजा है कि वह बढ़े तो उसे कोई रोक नहीं सकता । अगर सही मानों में हमें एक समाजवादी समाज की तरफ बढ़ना है तो वह तो बढ़ कर ही रहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता । सवाल यह है कि गिरते पड़ते बढ़ें, उलझावे में लपटे हुए बढ़ें या सुलझे हुए तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बढ़ें ।

DR. W. S. BARLINGAY (Bombay): It may be unnecessary.

डा० जेड० ए० अहमद : खैर, उसके बारे में फिर मैं अर्ज करूंगा कि नेसेसरी है या नहीं, ज़रूरी है या नहीं । अभी आप मुझको सुन लीजिये ।

[डा० जेड० ए० अहमद]

........तो यह बढ़ने वाला है इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती अगर सही मानों में हमें हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था को एक नई बुनियाद पर डालना है तो इसको बढाना है । अब, जैसा कि मैंने अभी कहा, जरूरत इस बात की है कि आंखें खोल कर हम देखें कि किस दिशा में बढ़ें, किस तरीके से बढ़ें । कितना वक्त लगाया जाय, किस चीज़ को पहले लिया जाय, किस चीज़ को बाद में लिया जाय, ये सब सवाल हमारे सामने आते हैं । आखें बन्द करके आप बैठे रहें और कहें कि हम तो समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मालूम नहीं किस तरफ आप बढ़ जायेंगे अगर आंखें बन्द करके आप बैठे रहें । मैं इस चीज़ के ऊपर ज्यादा जोर इसलिये देता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जिस तरीके से हमारे उद्योग चल रहे हैं अगर उनको वही उसी तरह छोड़ दिया जाये तो देश तरक्की नहीं कर सकता । हमारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं अभी वे प्राइवेट हैंड्स में हैं, ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो कि मोटे तौर पर उनको मुनाफे के लिये चलाते हैं । हमें जल्दी से जल्दी ऐसी हालत पैदा करनी है कि वे बड़े बडे उद्योग ऐसे लोगों के हाथों में न रहें ।

श्री जसौद सिंह बिष्ट (उत्तर प्रदेश) : चाहे उससे नुक्सान ही हो ।

डा० जेड० ए० अहमद : उसके अन्दर नुकसान नहीं है, मैं अर्ज करूंगा, आप घबड़ायें नहीं । आपने तो नागपुर प्रस्ताव पास किया है, हम तो उसका स्वागत ही करते हैं, आपने तो खुद अपना हाथ उठा कर उसको पास किया है ।

श्री हर प्रसाद सक्सेना : वह वहां, ऐसी जगहों पर नहीं जाते है ।

डा० जेड० ए० अहमद : अच्छा, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर वे बड़े बड़े उद्योग उन लोगों के हाथ में रह गये जो लोग कि मुनाफे के लिये उनको चलाते हैं तो फिर बहुत सी कठिनाईयों का सामना आपको करना पड़ेगा । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ न कुछ तबदीली आपको करनी पड़ेगी । हमारे दोस्त भूपेश गुप्ता ने कोल माइन्स का जिक्र किया । इसके अलावा टी गार्डेन्स को ले लीजिये, वह एक बहुत बड़ा उद्योग हमारा है जो कि विदेशी लोगों के हाथ में है । इसके अलावा बैंक्स हैं जिसमें कि विदेशी पूंजी लगी है । इसके अलावा हमारा आयात-निर्यात का उद्योग है जो कि बड़ी बड़ी कम्पनियों के हाथ में हैं जिनमें कि बहुत सी विदेशी कम्पनियां हैं और जो कि बड़े बड़े मुनाफे कमाती हैं । मैंने कल या परसों भी इसका जिक्र किया था कि इससे अरबों रुपया मुनाफे के तौर पर आता है लेकिन वह हमारे हाथ में नहीं आता कुछ लोगों के हाथों में चला जाता है, गायब हो जाता है । तो हमारी सरकार को इस बात को देखने की जरूरत है कि वह मुनाफा हमारे हाथ में आये ताकि हम मुल्क के विकास के लिये काम कर सकें । तो यह सवाल कि राज्य क्षेत्र, पब्लिक सैक्टर, फैले और इस तरीके से फैले कि मुनाफा जो पैदा होता है वह सरकार के हाथ में आये और उसके जरिये से हम अपने देश का विकास करें, हमारे सामने आता है और यह प्रश्न, यह सवाल, आज एक मुख्य प्रश्न हो गया है ।

श्री जसौद सिंह बिष्ट : इस मुनाफे में इन्कमटैक्स शामिल है या नहीं ?

डा० जेड० ए० अहमद : जी हां, मुनाफे पर इन्कमटैक्स लगता है लेकिन बहुत सा इंकमटैक्स दिया नहीं जाता है, गायब हो जाता है, उसके लिये गलत रिकार्डस पेश किये जाते हैं और इंकमटैक्स लेने के बाद भी उनके पास जो बच जाता है वह बहुत बड़ी बड़ी रकमें हैं । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह याद रखिये कि हमारी तीसरी योजना एक बहुत बड़ी योजना होने वाली है जैसा कि आपने नागपुर सेशन में तय किया है, तो फिर आपको

नये साधन पैदा करने पड़ेंगे । आप घड़ी घड़ी, हर वक्त, इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का सहारा नहीं ले सकते हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के ऊपर टैक्स लगा कर आप रुपया नहीं हासिल कर सकते हैं क्योंकि गरीबों के पास रुपया रहा नहीं है और मैं यह भी मानता हूं कि सिर्फ इंकमटैक्स का रेट बढ़ा बढ़ा कर अगर आप यह समझें कि साधन हासिल कर लेंगे तो वह भी नहीं चलने वाला है, ऐसी हालत में आपको साधन पैदा करने के नये सोर्सेज, नये जराये, नये तरीके निकालने पड़ेंगे और उसके लिये मैं समझता हूं कि स्टेट सैक्टर से, पब्लिक सैक्टर से, काफी रुपया हमको मिलना चाहिये और हमें ऐसी इंडस्ट्रीज का नैशनलाइजेशन करना चाहिये, ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये जो कि अपने देश के विकास के लिये हमें रुपया दे सकती हैं ।

अब साहब, हमारे दोस्त ने फरमाया कि साहब बहुत कंफ्युजन है, बहुत से उलझाव हैं । स्टेट ट्रेडिंग का सवाल आया और आप यह फर्माते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ एक बात कहते हैं और दूसरे मिनिस्टर कुछ दूसरी बात कहते हैं ।

श्री जसौद सिंह बिष्ट : उन्होंने फूडग्रेंस के बारे में कहा था ।

डा० जेड० ए० अहमद : जी हां, फूडग्रेंस की स्टेट ट्रेडिंग का जो उलझाव है उसके बारे में कहा । एक नहीं दस चीजों के बारे में उलझाव है । आपने इंडस्ट्रियल पालिसी के बारे में भी कुछ पढ़ कर सुनाया । मैं कहना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्रियल पालिसी का पेश कर देना एक चीज है लेकिन उस इंडस्ट्रियल पालिसी को अमल में लाना, बदलती हुई सूरतों में अमल में लाना, बदलती हुई हालतों में अमल में लाना, यह दूसरी चीज है, दूसरा सवाल है । मुझे तो ताज्जुब होता है कि जब कभी कोई अमली सवाल उठा दिया जाता है तो उन लोगों की तरफ से जो कि अमली तौर पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं जवाब यह मिलता है कि साहब, हमने अपनी नीति तो साफ कर दी है । साहब, नीति एक चीज है और नीति के ऊपर अमल करना दूसरी चीज है, नीति के ऊपर अमल करना एक दूसरा ही प्रश्न है । तो उस नीति के ऊपर कैसे अमल किया जाय इस सवाल के ऊपर वक्तन फवक्तन गौर करना पड़ेगा और उसके लिये आपको इस प्रकार की समितियां बैठानी पड़ेगी और ठोक पीट कर चीजों को देखना पड़ेगा और तभी आपकी नीति सही मानों में अमल में आयेगी वरना वह कागज पर ही रह जायगी, जैसा कि होता है । मेरी आलोचना तो यह है कि सरकार की नीतियां तो बहुत शानदार बनती हैं, उसके बयानात बहुत अच्छे निकलते हैं लेकिन जब वे अमल में आते हैं तो चूंकि उनकी पूरी छानबीन नहीं होती, चूंकि आप पतफसीलात में नहीं जाते, चूंकि हर एक चीज को उसकी बारीकियों में जाकर नहीं देखते और उसके ऊपर एक राय नहीं बनाते इसलिये इधर उधर खिचाव शुरू हो जाता है, कोई इधर खींचता है और कोई उधर खींचता है और नतीजा यह होता है कि वे एक दूसरे को काट देते हैं, वे आपस में न्युट्रलाइज हो जाते हैं और कोई चीज अमली तौर पर सामने नहीं आती है । तो यह मेरा पहला प्वाइण्ट है ।

दूसरा प्वाइण्ट जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज विदेशी सरमाया बाहर से हमारे यहां आ रहा है तो वह विदेशी सरमाया कैसे आवे, किन उद्योगों में उसको लगाया जाय, किस तरीके से विदेशी सरमाये का इस्तैमाल किया जाय, इस बारे में हमारी कुछ राय होनी चाहिये, उसके बारे में पार्लियामेंट की कुछ स्पष्ट नीति होनी चाहिये क्योंकि इस मामले में हर प्रकार का दबाव आता है । बाहर के लोग यहां आये तो उन्होंने कहा कि, साहब प्राइवेट सैक्टर को बढ़ाइये हम आपको रुपया देंगे, अगर आप प्राइवेट सैक्टर को नहीं बढ़ायेंगे तो नहीं देंगे । इसी तरह से वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में एक दबाव था, एक प्रेशर था कि

[डा० जेड० ए० अहमद]
आप प्राइवेट सैक्टर को बढ़ायें । तो इसको हम गलत समझते हैं । हमारी जो नीति है, औद्योगिक नीति है, उसके वे विरुद्ध जाते हैं । हम पब्लिक सैक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो रुपया आता है वह अपने साथ कुछ प्रेशर्स लाता है, अपने साथ कुछ दबाव लाता है ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SAPRU) in the chair]

हमारे सामने जो दबाव आता है उस दबाव का अगर हमें मुकाबला करना है तो फिर अपनी नीति को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिये । इसके लिये हमें देखना चाहिये कि यह रुपया, अन्दर का या बाहर का, किस उद्योग में जायगा ? प्राइवेट में जायेगा या पब्लिक में जायगा ? लेकिन अभी हमारी पालिसी में यह चीज साफ नहीं होती । इधर उधर का दबाव, कुछ उलझाव, कुछ घबराहट, मिल मिला कर कुछ ऐसी हालत पैदा करती है कि जिसमें हम अंधों की तरह टटोलते हैं और कुछ निकलता नहीं है । जाहिर है कि समाजवाद का लक्ष्य हमने साफ तौर से मान लिया है, बिल्कुल मान लिया है. . . . .

श्री टी० पाण्डे (उत्तर प्रदेश) : एक सवाल में इंफार्मेशन के लिये आपसे पूछना चाहता हूं । जैसा कि हमारा संविधान है उसके अनुसार अगर हम कम्पनीज़ को और फैक्टरीज़ को, कारखानों को नेशनलाइज करें तो उसके लिये हमें मुआवजा देना पड़ेगा । तो क्या भारत सरकार के लिये और इस गरीब मुल्क के लिये मुआवजा देकर नेशनलाइज करना मुनासिब है या जो मुआवजे के रूप में हम रुपया देते हैं उसको हम पब्लिक सैक्टर में नये कारखाने खोल कर इस्तेमाल करें यह मुनासिब है। दोनों में से कौन सा रास्ता इस गरीब मुल्क के लिये युक्तिपूर्ण है ?

डा० जेड० ए० अहमद : मैं इसका जवाब यही दूंगा कि मुआवजा कितना दिया जायगा वह विधान के मुताबिक देना पड़ेगा लेकिन मुआविजा कितना देंगे यह हमारी पार्लियामेंट, हमारी सरकार तय करेगी । जाहिर है कि जितना मुआवजा वे मांगते हैं उतना नहीं दिया जा सकता, दुनिया में कहीं भी कोई चीज नेशनलाइज की जाती है तो जितना मुआवजा मिल मालिक या उद्योगपति मांगते हैं उतना नहीं दिया जाता । जमींदारी अबालिश हुई लेकिन जितना मुआवजा जमींदार मांगते थे उतना नहीं दिया, उससे बहुत कम दिया । इसलिये मुआवजा देकर हम उद्योग को अपने हाथ में लेते हैं । लेने के बाद एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, जो पैदावार का साधन हमारे हाथ में आ जाता है, एक लम्बे अर्से को मद्देनजर रखते हुए, वह हमारे लिये ज्यादा फायदेमन्द होता है । अब सवाल यह है कि आप मुआवजा दें तो कितना दें, किस वक्त दें, उसको किस तरह से फेज़ आऊट करें—२० साल में, २५ साल में, ३० साल में । आखिर जमींदारी अबालिशन में भी चालीस, चालीस साल के बाण्ड दिये गये हैं । यह जरूर है कि आज अगर किसी चीज़ का राष्ट्रीयकरर किया जाय तो कल ही उसका मुआवजा लम्प सम में दिया जाय, मगर हमारा जो पर्स है उसको देख कर ही हम यह तय करेंगे । जो भी अमली कदम हम लें वह नीति के मुताबिक होना चाहिये, अमली कदम उस नीति के विरुद्ध नहीं जा सकता । हां, दुशवारियां होंगी और उन दुशवारियों का हम सामना करेंगे । लेकिन एक दिशा में हमें बढ़ना है । एक बार हमारी नीति स्पष्ट और साफ हो जाय, उसके बाद जो अमली गुत्थियां होंगी उनको भी हम सुलझा सकते हैं ।

आखिर में मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि हमने तय किया है कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे और अगर इस फैसले के कोई मानी हैं, इसका कुछ महत्व है, अहमियत है तो फिर नागपुर सेशन के बाद हमें फौरन अपनी अर्थ व्यवस्था के एक एक पहलू के ऊपर गौर करना है । सबसे महत्वपूर्ण पहलू आज

यहां के औद्योगीकरण का पहलू है—हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, हमारे उद्योग कमजोर हैं। हम तेजी से औद्योगीकरण करना चाहते हैं और इसीलिये नागपुर सेशन के बाद राम सहाय जी ने आज जो रिजोल्यूशन पेश किया है यह न सिर्फ बहुत उचित है बल्कि इसकी खास अहमियत है। समाजवाद की तरफ बढ़ने के लिए औद्योगीकरण को देखो कि वह किस तरफ जाने वाला है, कौन सा रास्ता उसको अख्तियार करना है। उसके लिए एक नक्शा बनाइये, पांच, छः, सात, आठ साल का नक्शा बनाइये और इसके लिए एक कमेटी रखिये जो प्लानिंग करे। उसमें जिम्मेदार लोग, पार्लियामेंट के मेम्बर हों, टेकनिशियंस हों, जानकार और तजुर्बेकार लोग हों।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SAPRU): Why should we not have co-ownership: 51 per cent. State and 49 per cent. private.

डा० जेड० ए० अहमद : यह सब मसला उस कमेटी के सामने पेश किया जा सकता है। आप उसकी किस चीज को सौ फी सदी करें या आरजी तौर पर उसको अधूरा रखें और पांच साल बाद फिर सौ फी सदी रखें यह कमेटी के सोचने की चीज है। लेकिन कमेटी अपाइंट करने से इंकार करना मैं समझता हूं बिलकुल ग़लत है। यह वही लोग करते हैं जो घबड़ाते हैं इस बात से कि मुमकिन है यह कमेटी कोई ऐसी बात कह दे जो ज्यादा राष्ट्रीयकरण की तरफ ले जाय या ज्यादा राजकीय क्षेत्र की तरफ ले जाय। मैं उन सब दोस्तों से अपील करता हूं कि आप घबड़ाएं नहीं। अक्सर यह होता है कि तरक्की के रास्ते में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, लोग डरते हैं कि कहीं कुछ हो न जाय और जो लोग डरते हैं वे दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकते।

DR. W. S. BARLINGAY: The Industrial Policy is quite clear to the Government.

डा० जेड० ए० अहमद : मैं यह चाहता हूं कि अगर यह क्लीयर है तो उसको और क्लीयर कर दिया जाय। इसलिए राम सहाय जी का जो प्रस्ताव है, मेरे ख़याल से उसको एक मत से पूरे हाऊस को मान लेना चाहिये।

श्री पां० ना० राजभोज (मुम्बई) : उपसभाध्यक्ष जी, मेरे मित्र राम सहाय जी जो प्रस्ताव यहां लाये हुए है मेरे ख़याल से अच्छा है क्योंकि मैं समझता हूं कि कमेटी बने और उसके सामने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात रखी जाय तो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। चाहे कम्यूनिस्ट हों, चाहे सोशलिस्ट हों, किसी से भी यह गवर्मेन्ट नहीं डरती। सबको हमने हजम कर लिया है। वे लोग सोचते हैं हर एक चीज जो गवर्मेन्ट अच्छी करती है वह उनकी वजह से है और बात बात में क्रिटिसिज्म करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार इस चीज को नहीं जानती, वह अच्छी तरह से जानती है। आपका रंग, आपकी बात, आपका रहन सहन, आपका रिवाज, सब कुछ हम लोग जानते हैं। हमारी गवर्मेन्ट एक सीधे रास्ते पर चलती है। हमारे माननीय मित्र राम सहाय जी ने कई उदाहरण देकर बताया है कि हमारी सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला में कारखाने स्थापित करके कितनी प्रगति की है। यहां समाजवादी समाज की रचना का हमारा लक्ष्य है वह हमारे देश की परिस्थिति को देखकर धीरे धीरे प्राप्त करना है। उस नीति पर चलकर कोई नुकसान नहीं है। इस प्रस्ताव द्वारा हम चाहते हैं कि देश में जो कई प्रकार के रोजगार और उद्योग धंधे हैं जैसे कोयला है, सीमेंट है, जूट है, इन उद्योगों के विषय में जांच करने के लिए कमेटी बैठेगी और उनके राष्ट्रीयकरण किये जाने की संभावना पर विचार करेगी। इस तरह की बात होने में कोई नुकसान नहीं है। नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें कृषि संगठन के ढांचे के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं कि सीलिंग कितनी रखनी चाहिये, जमींदारों की कितनी भूमि रहनी चाहिये,

[श्री पां० ना० राजभोज]
आदि। मैं भी चाहता हूं कि समाजवादी समाज की रचना होनी चाहिये और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मिलमालिक हैं और जो कालाबाजार करने वाले लोग हैं उनकी जांच होने की बहुत आवश्यकता है।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार): राष्ट्रीयकरण की बात कहिए।

श्री पां० ना० राजभोज: कमेटी की बात मैं कर रहा हूं, मेरे भाई। जब हम समिति नियुक्त करेंगे और वह कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद गवर्मेन्ट देखेगी कि उसको क्या करना है। हमारे शाह साहब और दूसरे लोग यह भय देते हैं कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है, इससे बड़ा नुकसान है। लेकिन समाजवादी समाज आदि हम चाहते हैं तो मेरे खयाल से हमें पूंजीपतियों की जांच करनी चाहिये। जिन लोगों के पास कई प्रकार के मकान हैं उनके मकानों के ऊपर भी कोई सीलिंग होनी चाहिये, जिन लोगों के पास धन सम्पत्ति है, करोड़ों रुपया है उनके ऊपर भी किसी न किसी तरह से सीलिंग बैठाना चाहिये। इसलिए उनके बारे में एक कमेटी बैठाना मेरे खयाल से बहुत आवश्यक है।

उपसभाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसका उद्देश्य तथा उसका ध्येय यह है कि आज की परिस्थिति में देश के कौन कौन से उद्योग धंधे हैं जिनका समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, द्वितीय पंचवार्षिक आयोजना की पिछले तीन साल की प्रगति को देखते हुए तथा अगले दो वर्ष की बात पर विचार करके तथा तृतीय पंचवार्षिक आयोजना की तैयारी करने के लिये कुछ नये धंधों का तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बहुत ही आवश्यक है।

शुरू शुरू में ही मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। वह इसलिये कि प्रथम पंचवार्षिक आयोजना की गरज तथा आवश्यकता देख कर ही सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण करके शेअरहोल्डर्स तथा अन्य जनताके पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिये था उसके सिलसिले में कार्यवाही की। जो फायदा था वह आम जनता के सेवार्थ उपयोग में आ गया। दूसरी बात है स्टेट बैंक आफ इंडिया की। उससे बैंकों की सुविधा देहातों में देने के लिये तथा रिजर्व बैंक के एजेंट नियुक्त करके एक बड़ा काम हो गया है। मैं यह कह रहा था कि जब जब आवश्यक हुआ तब तब सरकार ने प्रगतिशील तथा समयोचित धारणा रखी है। इसके बारे में कोई भी शक नहीं है।

इस संदर्भ में इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन की जांच होनी चाहिये। इस समय हमारे उद्योग में पबलिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और मिक्स्ड इकानामी, इन तीन विभागों के करने से एक समस्या पैदा हो गई है। इसलिए इन्हीं कार्यों की एक एक रेखा लगा के हमने कोएग्जिस्टेंस का आचरण किया है। यह सरकारी प्रस्ताव हमने संसद में सोचा था तब यह बताया गया था कि यह जो पब्लिक सेक्टर है उसको बढ़ाया जा सकता है यदि उसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता है या नहीं यह मालूम करने के लिए यह समिति नियुक्त करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वह सरकार तथा प्लानिंग कमिशन को सलाह दे और सिफारिश करे। मै मानता हूं कि सरकार को इस तरह की समिति बनाने में कोई एतराज नहीं होगा। हम सब उद्योग धन्धों का समाजीकरण नही करेंगे बल्कि जो उद्योग धन्धे खानगी जायदाद बने हुए हैं, जो ठेकेदारी बनी है, जिनमें कालाबाजार होता है, उनमे सुधार करने की बात को ध्यान में रखते हुए कि वे अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा रहे है या नही या उन में किसी प्रकार का कोई दोष तो नही आ गया है, हम सब चीजों को बताने का मौका देंगे। समाजीकरण की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब वह धंधा या वह उद्योग दोषमय बनता है। देख

की रचना के लिये तथा औद्योगिकरण के लिये जो आवश्यक धंधे हैं जैसे कि इस्पात वह तो सरकारी मालमत्ता है किन्तु ऐसे भी धंधे हैं जो अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाये हैं । मेरे ख़याल से इस चीज की खोज और जांच होनी चाहिये । मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूं । उनको भी कुछ हिस्सा पंचवर्षीय योजना में दिया गया है और देना चाहिये, यह बात मैं मानता हूं । किन्तु मैं देखता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ दोष निर्माण हुए हैं पहला दोष यह पैदा हुआ है कि ये लोग लाभ की आशा से व्यवसाय में धन लगाते है, खरीद और बिक्री करते है जिसको स्पेक्युलेशन कहते हैं । इस स्पेक्युलेशन में न प्रोफिट दिखाई देता है और न ही कर देना पड़ता है । इसलिए यह देखना चाहिये कि कौन कौन से उद्योग-धंधे हैं जो सिर्फ स्पेक्युलेशन से ही चलते हैं । मैं आपको उदाहरण देकर इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करूंगा । मान लीजिये ६ व्यक्ति किसी कपड़े के कारखानों के ठेकेदार हैं और वे इन मिलों को नियंत्रण करते हैं । इसलिये उनको काफ़ी रुई की ज़रूरत है । वह काटन एक्सचेंज में जाता है और वहां अपने दोस्तों के नाम पर रुई खरीदता है । जब मंडी की परिस्थिति अच्छी है तो वह फायदा उठाता है और जेब में पैसा डालता है ।

(Interruptions.)

आप पहले बात सुनने की कोशिश कीजिये । इस तरह से वह मिल मालिक कर के रूप में सरकार को एक नया पैसा भी नहीं देता है । जब मंडी की परिस्थिति अच्छी न हो तब वह सब माल मिलों को भेज देता है और उसको कुछ नुकसान नहीं होता है । जैसी बात इस तरह के मिलों में होती है उसी तरह की बात और धंधों में भी होती होगी । महंगी चीज़ खरीदने से फायदा नही होता और सारी इंडस्ट्री को खतरा पहुंचता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो लोग इस तरह से कालाबाजार करते हैं, इस तरह से जो मैनेजिंग डायरेक्टर फायदा उठाते हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ रोशनाई लगाने के लिए कोई रास्ता अवश्य ढूंढना चाहिये ताकि वे इस तरह की बातें न करें । मिलमालिक हमारे दुश्मन नहीं हैं मगर इन लोगों ने अनाज की स्थिति को कितना खराब कर दिया है । जिस तरह से सरकार अनाज की पालिसी के बारे में कुछ न कुछ रास्ता निकाल रही है उसी तरह से हमें उद्योगधंधों में जो लोग इस तरह का कालाबाजार करते हैं उनके बारे में भी कोई न कोई रास्ता निकालना होगा ।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस ने नागपुर में जो प्रस्ताव पास किया है उससे हम देश में एक नये ढंग की समाज रचना करने जा रहे हैं । अनाज के बारे में सरकार ने जो कार्यवाही की है उसके खिलाफ व्यापारियों न कुछ बातें की हैं मगर सरकार इन सब बातों का सामना कर रही है और यह खुशी की बात है कि अनाज की हालत धीरे धीरे सरकार के काबू में आती जा रही है । कांग्रेस ने जो रास्ता अख्तियार किया है वह बिल्कुल सही रास्ता है । उसका रास्ता पहले से ही यही था वह अपने रास्ते से हटी नहीं है । आप लोग ही बिगड़े हुए हैं मगर यह आनन्द की बात है कि अब आप लोग हमारे रास्ते में आ रहे हैं । यह एक सौभाग्य की बात है कि आप लोग कांग्रेस के रास्ते पर आ रहे हैं जो कि एक ठीक बात है । कांग्रेस भी धीरे धीरे देश में समाजवाद की रचना कर रही है और प्रगतिशील बनने की कोशिश कर रही है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि इस तरह कालाबाजार करने से सरकार को २०० से ३०० करोड़ रुपये का नुकसान होता है । यह समिति का कार्य होगा कि वह एक एक उद्योगधन्धे में और मिलों में इस बात को देखे कि इस तरह का कालाबाजार तो वहां पर नहीं चल रहा है ।

मेरी प्रार्थना है कि तृतीय पचवर्षीय योजना के लिये यदि पैसा चाहिये तो जीवन की आवश्यक चीजें सस्ती हों और लोगों को नित्य मिलती रहें

[श्री पा० ना० राजभोज]

तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हमें देश में कई उद्योगधंधों का समाजीकरण करना होगा। अनाज का उद्योगधंधा हमने हाथ में लेने का निश्चय किया है। इसके साथ ही साथ मिल का कपड़ा भी हाथ में लेना होगा क्योंकि यह दोनों धंधे बहुत आवश्यक हैं। बैंकिंग है जिसका पैसा इतना है कि वह पब्लिक सेक्टर में आता नहीं है। सीमेंट, कागज और इसी प्रकार कई अन्य धंधे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनको पब्लिक सेक्टर में लेना ही चाहिये या सहकारिता के ढंग पर चलाया जाना चाहिये ताकि जनता और मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। सरकार जो कर लगाती है उसका पालन हो तथा हमारा समाजवाद सब नीतियों का समन्वय करके आगे बढ़े।

नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया है वह तीसरी पंच वर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सब प्रकार की जांच कर रही है ताकि देश ठीक प्रकार से आगे बढ़ता चले। आप लोग कहते हैं कि चीन और रूस में स्टैबलिटी स्थापित हो गई है। मेरा आप से कहना है कि हमारी सरकार जो प्रगति कर रही है वह धीरे धीरे देश की परिस्थितियों को सामने रखकर कर रही है। हमारे दोस्त तो बाहर पैसा लेकर प्रोपेगन्डा करते हैं, इस तरह का काम नहीं होना चाहिये। देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सब लोगों का उसमें सहयोग होना चाहिये। कांग्रेस ने नागपुर में जो प्रस्ताव पास किया है उसी के आधार पर इस तरह की कमेटी कायम की जा सकती है जो कि उद्योगधंधों को लेने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह से हमने अनाज का व्यापार अपने हाथ में ले लिया है उसी तरह से हमें अन्य धंधों को भी अपने हाथ में लेना होगा। यह इसलिए आवश्यक है कि बगैर इन चीजों को अपने हाथ में लिये हम देश में समाजवाद की रचना नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस बदली नहीं है, उसका दिमाग वही है जो पहले था। मगर तुम्हारा दिमाग बदल रहा है।

डा० जेड० ए० अहमद : आप कांग्रेसी कब से हुए ?

श्री पा० ना० राजभोज : आपके सर पर सफेद टोपी देखकर मुझे आनन्द होता है। श्री राम सहाय जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा और हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने उसके सम्बन्ध में जो बातें कहीं वे बहुत अच्छी हैं लेकिन आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। आपको यह देखना चाहिये कि आपका दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में ठीक हो। हमारे विरोधी पक्ष के भाई कहते हैं कि कांग्रेस का नागपुर वाला प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस बराबर यही कहती आ रही है कि वह देश में समाजवाद की रचना करना चाहती है और उसमें सब देशवासियों को सहयोग देना चाहिये। मेरी विरोधी पक्ष के लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग भगवान बुद्ध के बताये हुए रास्ते को अपनायें और अपना दिल व दिमाग उस तरफ लगायें। श्री राम सहाय जी ने जो प्रस्ताव यहां सदन में उपस्थित किया है उससे हमारी पार्टी में किसी प्रकार की मुखालफत होने वाली नहीं है। हमारे कम्यूनिस्ट भाई ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भाषण दिया वह अच्छा है मगर मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पहले से जो नीति बतलाई है वह उसी नीति पर कायम है और धीरे धीरे उस पर चल रही है। हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिस नीति से देश को आगे बढ़ा रहे हैं उससे देश में समाजवाद की रचना होने जा रही है। मगर इस चीज के लिए यह आवश्यक है कि देश में जो उद्योगधंधे हैं उनके बारेमें जांच की जाय। श्री राम सहाय जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह एक ऐसी समिति की

रचना के बारे में है जो देश में उद्योग धंधों में फैले हुए भ्रष्टाचार की जांच करके उनके राष्ट्रीयकरण की सिफारिश करे। हमारे पूज्य प्रधान मंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा कि हम सब लोगों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिये। यह जो प्रस्ताव श्री राम सहाय जी ने रखा है वह एक जरिया है देश को समाजवाद की ओर ले जाने का। हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं और हमारे चीफ़ विप भी आ गये हैं और मुझे आशा है कि वे कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल लेंगे जिससे इस प्रस्ताव की जो भावना है वह कायम हो सके। मुझे आशा है सरकार यह प्रस्ताव मंजूर करेगी। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

ANNOUNCEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): Sir, with your permission, I rise to announce that Government business in this House for the week commencing 16th February, 1959 will consist of—

(1) Further discussion of the Motion of Thanks on President's Address. Reply to the debate will be made on Tuesday, the 17th February, 1959, after the question hour.

(2) Further consideration and passing of the Cinematograph (Amendment) Bill, 1958, as passed by Lok Sabha.

(3) Consideration and passing of the following Bills—

(i) Cost and Works Accountants Bill, 1958, as reported by the Joint Committee.

(ii) Delhi Land Reforms (Amendment) Bill, 1959, as passed by Lok Sabha.

(iii) Delhi Panchayat Raj (Amendment) Bill, 1959, as passed by Lok Sabha.

(iv) Pharmacy (Amendment) Bill, 1959, as passed by Lok Sabha.

As Members are already aware, the Railway Budget for 1959-60 will be laid on the Table on the 18th February, 1959, at 1 P.M.

ENQUIRY REGARDING MOTION FOR DISCUSSION ON THE VISIT OF THE FINANCE MINISTER TO CANADA, U.S.A. AND THE U.K.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I have a submission to make. For the last two Sessions, I have been wanting a discussion on the visit of the Finance Minister to Canada, the U.S.A. and the U.K. and this has been kept pending as a No-Date-Mentioned Motion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SAPRU): You may raise the point later on.

SHRI BHUPESH GUPTA: The discussion could not be held last Session, because, due to illness, Mr. Morarji Desai could not be present.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SAPRU): You may raise this at 2-30 P.M.

SHRI BHUPESH GUPTA: Then you will not allow me to raise the point. Since the hon. Minister is present now, I would like him to kindly arrange for a discussion so that this does not lapse this time also. He will be, I hope, good enough to see to that.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): The Session has just started. Let my hon. friend have some patience . . .